D.T.U. Dues to N.D.M.C.

1357. { **Shri Vishram Prasad:** / **Shri R. G. Dubey:** }

Will the Minister of **Transport** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that N.D.M.C. has demanded from D.T.U. a sum of Rs. 1,20,000;

(b) whether it is also a fact that the Chairman, N.D.M.C. has threatened to take direct action against D.T.U. in case of failure to pay this amount; and

(c) if so, the action taken in the matter?

The Minister of Shipping in the Ministry of Transport (Shri Raj Bahadur): (a) Yes. According to the information furnished by the New Delhi Municipal Committee, the D.T.U. owes the Committee a sum of Rs. 1,91,850 towards tehbazari in respect of its Bus Queue shelters located on Municipal land in New Delhi for the period ending 31-10-63.

(b) and (c). The Delhi Transport Undertaking was informed by the New Delhi Municipal Committee that if the Undertaking failed to pay the dues, necessary action would be taken to realise the dues and to remove the queue shelters within its jurisdiction. However, the Committee reports that it is now proposed to settle the matter by mutual agreement and consultation.

चूहे पैदा होने को रोकने की योजना

१३५८. { **श्री ओंकारलाल बेरवा :** / **श्री गोकरन प्रसाद :** }

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने चूहों की पैदाइश रोकने की कोई योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये कितनी राशि नियत की गई है ;

(ग) यह योजना किन किन स्थानों पर आरम्भ की गई है ; और

(घ) क्या दूसरे देशों ने चूहों की मांग भेजी है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां। भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् ने उपयुक्त नियन्त्रण उपायों को निकालने के विचार से खेत के चूहों का अध्ययन करने के लिए एक समन्वित अनुसंधान योजना मंजूर की है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारें चूहों के नियन्त्रण के लिए लगातार प्रयत्न कर रही हैं और उन्होंने नियत रूप से बड़े पैमाने पर अभियान चलाये हैं और चला रही हैं।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने १ अप्रैल, १९५९ से ३१ मार्च, १९६५ तक इस समन्वित योजना के लिए २,८८,९७०रुपये की राशि की मंजूरी दी है। राज्य सरकारों के द्वारा चूहों के नियन्त्रण के लिये प्रयोग हुई कृन्तकनाशियों के मूल्य का आधा हिस्सा भारत सरकार देती है।

(ग) यह समन्वित अनुसन्धान योजना पांच केन्द्रों में चल रही है अर्थात् लुधियाना (पंजाब), कानपुर (उत्तर प्रदेश), हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश), कोम्बेतूर (मद्रास) और बम्बई (महाराष्ट्र)। चूहों के विरोध में अभियान प्रायः सभी राज्यों और संघीय राज्यों में चलाये गये हैं।

(घ) जी नहीं।

Zila Parishads

1359. Dr. L. M. Singhvi: Will the Minister of **Community Development and Cooperation** be pleased to state: